

संख्या-2551/छ:-पु0-9-14-31(47)/2014

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- ✓1-सचिव,  
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,  
लखनऊ।
- 2-पुलिस महानिदेशक,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3-अपर पुलिस महानिदेशक,  
उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,  
इलाहाबाद।

गृह (पुलिस) अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक: 26 अगस्त, 2014

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-2015 के व्यय हेतु अनुदान संख्या-26, गृह विभाग पुलिस के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष की धनराशि पुलिस मुख्यालय के निस्तारण पर रखा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक किमिनल रिट याचिका संख्या-129/ 2006 लक्ष्मी बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014 (victim compensation scheme) के अन्तर्गत तेजाब हमलों, बलात्कार, मानव तस्करी अथवा हत्या आदि के मामलों में आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में प्राविधानित रू0 2.00 करोड़ की धनराशि गृह (पुलिस) अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-2439/6-पु0-7-14-2बजट/2013टी0सी0 दिनांक 23 जुलाई, 2014 द्वारा पुलिस मुख्यालय के निवर्तन पर रख दी गयी है।

2- इस संबंध में गृह (पुलिस) अनुभाग-7 द्वारा निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 23 जुलाई, 2014 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)  
सचिव।

Sri D. Ran

Put up on 15/9/14  
11/9/14

3308  
11-9-14

दी

संख्या- 24 39/6-पु-7-14-2बजट/2013टीसी

प्रेषक,

अखिलेश त्रिवेदी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,

इलाहाबाद।

गृह (पुलिस) अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2014

**विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 के व्यय हेतु अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष की धनराशि पुलिस मुख्यालय के निस्तारण पर रखे जाने की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रथम चार माह (अप्रैल, 2014 से जुलाई, 2014 तक) के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष होने वाले व्यय को वहन किये जाने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14.03.2014 में उल्लिखित शर्तों के अधीन शासनादेश संख्या-1142/6-पु-7-14-2बजट/2013टीसी, दिनांक 02.04.2014 द्वारा पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के निवर्तन पर अनुदान संख्या-26 के अन्तर्गत विभिन्न लेखाशीर्षों के विभिन्न मदों में राजस्व/पूँजी मतदेय पक्ष के लिए प्रावधानित धनराशि में से रखी गयी धनराशि रु0 37,38,00,33,000/- (रूपये सैंतीस अरब अड़तीस करोड़ तैंतीस हजार मात्र) एवं राजस्व भारित मद से धनराशि रु0 25,00,000/- (रूपये पच्चीस लाख मात्र) एवं शासनादेश संख्या-1148/6-पु-7-14-2बजट/2013टीसी, दिनांक 02.04.2014 द्वारा पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के निवर्तन पर अनुदान संख्या-26 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष '2055-पुलिस आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-05-लोक सभा निर्वाचन के विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि रु0 2,92,47,00,000/- (रूपये दो अरब बानबे करोड़ सैंतालीस लाख मात्र) को घटाते/समायोजित करते हुए शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में उल्लिखित



शर्तों के अधीन अनुदान संख्या-26 के अन्तर्गत विभिन्न लेखाशीर्षों के विभिन्न मदों में राजस्व/पूँजी मतदेय पक्ष के लिए प्रावधानित धनराशि में से रू0 1,15,79,60,20,000/- (रूपये एक खरब पन्द्रह अरब उन्चासी करोड़ साठ लाख बीस हजार मात्र) एवं राजस्व भारित मद से रू0 75,00,000/- (रूपये पचहत्तर लाख मात्र) जिसका विवरण संलग्नक में उल्लिखित है, को उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उपरोक्त धनराशियों का प्रदेश अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, जिसके करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों अथवा किसी अन्य अस्थायी आदेशों से शासकीय अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, जहां आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (2) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एकमुश्त प्रावधानित धनराशि को व्यय करने के पूर्व उन योजनाओं हेतु शासन की अनुमति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- (1) वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट में पुलिस मुख्यालय के निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि में 'व्यय की नई मदों' के माध्यम से प्राप्त धनराशि भी सम्मिलित है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि रू0 हजार में)

क्रं.	विवरण	लेखाशीर्ष	धनराशि
1	प्रदेश के 09 प्रशिक्षण संस्थानों, 13 जनपदीय व 18 पीएसी स्थायी आरटीसी तथा 62 जनपदीय एवं पीएसी अस्थायी आरटीसी पर कम्प्यूटर लैब की स्थापना	2055-पुलिस आयोजनेत्तर-003-शिक्षा और प्रशिक्षण-04-शिक्षा और प्रशिक्षण-मुख्य-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	5000
2	प्रदेश के 10 जनपदों एवं 03 प्रशिक्षण संस्थानों में 33 अश्वों तथा जनपदों/वाहिनियों में 73 श्वानों का क्रय किया जाना	2055-पुलिस आयोजनेत्तर-109-जिला पुलिस-03-जिला पुलिस-मुख्य-08-कार्यालय व्यय	6950
3	जनपद मेरठ के रेहटा में एक नये थाने की स्थापना	2055-पुलिस आयोजनेत्तर-109-जिला पुलिस-03-जिला पुलिस-मुख्य-01-वेतन	1237

		03-मॅहगाई भत्ता	1113
4	जनपद गाजियाबाद के लोनी बार्डर, ट्रोनिा सिटी तथा खोड़ा में नये थानों की स्थापना	2055-पुलिस आयोजनेत्तर-109-जिला पुलिस-03-जिला पुलिस-मुख्य- 01-वेतन	3711
		03-मॅहगाई भत्ता	3340
5	प्रदेश के समस्त तहसील मुख्यालयों 354 जनपदीय थाने तथा जीआरपी अनुभाग के 13 क्षेत्राधिकारी कुल 367 फोटोकापियर मशीन के क्रय किया जाना	2055-पुलिस आयोजनेत्तर-109-जिला पुलिस-03-जिला पुलिस-मुख्य-	5000
		12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	
6	जनपद बलरामपुर के उतरौला तहसील मुख्यालय पर फायर स्टेशन की स्थापना	2070-अन्य प्रशासनिक सेवार्ये- आयोजनेत्तर-108-अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण-03-प्रशासन- 01-वेतन	1000
		03-मॅहगाई भत्ता	1000
7	उ0प्र0 पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2014 के अन्तर्गत तेजाब हमलों, बलात्कार, मानव तस्करी अथवा हत्या आदि के मामलों आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-आयोजनेत्तर-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम- 09-तेजाब हमलों, बलात्कार, मानव तस्करी अथवा हत्या के प्रकरणों में आर्थिक सहायता-	20000
		42-अन्य व्यय	
<b>योग</b>			<b>48351</b>

(2) 'व्यय की नई मदों' के माध्यम से प्राप्त धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना पर ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत लेखाशीर्षक/इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

4- धनराशि व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.07.2014 के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4

*Handwritten signature*



4

5- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
( अखिलेश त्रिवेदी )  
उप सचिव।

संख्या- ~~2439~~ (1)/6-पु-7-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा/आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण/फायर सर्विस/पीएसी/सीबीसीआईडी, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना विभाग/भ्रष्टाचार निवारण संगठन/अर्थ विषयक अभिसूचना इकाई/रेलवे पुलिस/तकनीकी सेवार्ये/विशेष जांच, उ0प्र0, लखनऊ।
6. सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. गृह (पुलिस) अनुभाग-1, 2, 6, 8, 9, 10 एवं गोपन अनुभाग-2/3

आज्ञा से,  
( अखिलेश त्रिवेदी )  
उप सचिव।

शासनादेश संख्या- 2439/6-पु-7-14-2बजट/2013टीसी, दिनांक 23 जुलाई, 2014 का संलग्नक

(धनराशि रु0 हजार में)

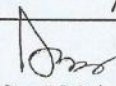
लेखाशीर्ष	वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु स्वीकृत धनराशि
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-001-निदेशन और प्रशासन-03-मुख्य	242402
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-003-शिक्षा और प्रशिक्षण-04-शिक्षा और प्रशिक्षण-मुख्य	1334515
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-101-आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता-03-अभिसूचना अनुभाग-मुख्य	1975585
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-101-आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता-04-अनुसंधान अनुभाग-01-भ्रष्टाचार निवारण संगठन	158733
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-101-आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता-04-अनुसंधान अनुभाग-02-अर्थ विषयक अभिसूचना एवं अनुसंधान इकाई	168384
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-101-आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता-04-अनुसंधान अनुभाग-03-अनुसंधान की अपराध शाखा तथा अन्य इकाईयां	514749
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-101-आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता-04-अनुसंधान अनुभाग-04-राज्य अपराध सूचना केन्द्र	47753
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-101-आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता-04-अनुसंधान अनुभाग-05-शोध एवं सांख्यिकीय इकाई तथा अंगुलि चिन्ह ब्यूरो	36465
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-101-आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता-04-अनुसंधान अनुभाग-06-स्पेशल टास्क फोर्स	8500
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-101-आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता-04-अनुसंधान अनुभाग-07-विशेष अनुसंधान दल	49017
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-101-आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता-04-अनुसंधान अनुभाग-08-आतंकवाद निरोधक दस्ता	155055
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-101-आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता-04-अनुसंधान अनुभाग-09-सुरक्षा शाखा	614988
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-104-विशेष पुलिस-03-राज्य सशस्त्र कान्सटेबुलरी-मुख्य	16234051
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-104-विशेष पुलिस-06-इण्डिया रिजर्व वाहिनी का गठन	400021
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-104-विशेष पुलिस-07-उ0प्र0 विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी	278178
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-108-राज्य मुख्यालय पुलिस-03-राज्य पुलिस मुख्यालय	343187
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-109-जिला पुलिस-03-जिला पुलिस-मुख्य	75467426
(भारित)	7000
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-109-जिला पुलिस-04-राज्य रेडियो अनुभाग-मुख्य	2683833



2055-पुलिस आयोजनेत्तर-109-जिला पुलिस-05-मोटर परिवहन अनुभाग-मुख्य	2892187
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-109-जिला पुलिस-06-वाराणसी में नदी पुलिस से सम्बन्धित भारत सरकार द्वारा वहन किये जाने वाला व्यय	11307
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-109-जिला पुलिस-07-जिला पुलिस (धाना)	367940
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-109-जिला पुलिस-08-जीआरपी थाना पुलिस	9989
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-110-ग्राम पुलिस-03-ग्राम पुलिस अधिष्ठान	1184134
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-111-रेलवे पुलिस-03-मुख्य	2586108
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-113-पुलिस कार्मिकों का कल्याण-03-पुलिस कार्मिकों की सुख सुविधा	40000
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-113-पुलिस कार्मिकों का कल्याण-04-चिकित्सालय व्यय-01-जिला पुलिस	201334
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-113-पुलिस कार्मिकों का कल्याण-04-चिकित्सालय व्यय-02-राज्य सशस्त्र कान्टेबुलरी	125762
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-113-पुलिस कार्मिकों का कल्याण-05-खेलकूद निधि तथा खेलकूद समारोहों एवं टूर्नामेंट आदि के सम्बन्ध में व्यय	3000
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-113-पुलिस कार्मिकों का कल्याण-06-पुलिस वेनीवेलेंट फण्ड के लिए अनुदान	3000
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-113-पुलिस कार्मिकों का कल्याण-08-शिक्षा सम्बन्धी पुलिस कल्याण की मदों पर व्यय	3000
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-113-पुलिस कार्मिकों का कल्याण-09-पुलिस कल्याण के लिए विशिष्ट अनुदान	40000
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-114-बेतार और कम्प्यूटर-03-पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र	628692
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-115-पुलिस बल का आधुनिकीकरण-03-राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाला व्यय	470547
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-116-न्यायालयिक विज्ञान-03-विधि विज्ञान प्रयोगशालायें	173806
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-भारत सरकार की ओर से रखा गया पुलिस दल (अपराधिक जांच और सतर्कता)	213840
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-04-भारत सरकार की ओर से रखा गया पुलिस दल-जिला पुलिस	17
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-05-लोक सभा निर्वाचन	2924700
2055-पुलिस आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-10-नक्सल प्रभावित जनपदों में सुरक्षा कार्यों पर व्यय (भारत सरकार की एस.आर.ई. स्कीम)	104928
2070-अन्य प्रशासनिक सेवार्यें-108-अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण-03-प्रशासन (भारत)	2642969
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम	500
03-कर्तव्य पालन के दौरान मारे गये/घायल हुए पुलिस/अग्निशमन सेवा के कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रह भुगतान	60000
04-असामाजिक तत्वों द्वारा मारे गये/घायल हुए व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह भुगतान	5000

*Handwritten signature*

05-पुलिस की हिंसा विरोधी कार्यवाही के फलस्वरूप मारे गये/घायल हुए गैर सरकारी व्यक्तियों को/आश्रितों को आर्थिक सहायता	5000
06-रेल दुर्घटना में मृत/घायलों के परिवारों को सहायता	1
07-हिंसक वन्य पशुओं द्वारा मारे/घायल किए गए व्यक्तियों एवं मवेशियों के मालिकों को मुआवजा का भुगतान	1000
09-तेजाब हमलों, बलात्कार, मानव तस्करी अथवा हत्या के प्रकरणों में आर्थिक सहायता	20000
10-पुलिस द्वारा मानवाधिकार हनन के प्रकरणों में मृतक/घायल के आश्रितों/पीड़ितों को आर्थिक सहायता	40000
11-दंगा पीड़ितों की सहायता	120000
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-लोक व्यवस्था प्रभावित करने वाली आतंकवादी घटनायें-अग्निकाण्ड आदि	100000
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-04-लावारिश शवों के अन्तिम संस्कार हेतु व्यवस्था	4000
2251-सचिवालय सामाजिक सेवार्य- 090-सचिवालय-03-नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु मशीनरी का सुदृढ़ीकरण	60917
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय- 207-राज्य पुलिस-03-गृह (पुलिस) विभाग की विभिन्न इकाइयों के निर्माण कार्य हेतु व्यवस्था	40000
कुल योग (मतदेय)	<b>115796020</b>
कुल योग (भारित)	7500

  
( अखिलेश त्रिवेदी )  
उप सचिव।  
✓





# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग—4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 9 अप्रैल, 2014

चैत्र 19, 1936 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-9

संख्या 653/छ:-पु०-9-14-31(90)-2010

लखनऊ, 9 अप्रैल, 2014

अधिसूचना

प0आ10-119

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 357-क द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल केन्द्र सरकार से समन्वय करके एतद्वारा ऐसे पीड़ितों या उनके आश्रितों, जिन्हें अपराध के कारण हानि या क्षति हुई है और पुनर्वास की आवश्यकता है, को क्षतिपूर्ति देने के प्रयोजनार्थ निधि उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित योजना बनाते हैं अर्थात्—

### उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना

1—यह योजना उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2014 कही जायेगी।

2—जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस योजना में—

संक्षिप्त नाम,  
परिभाषाएँ

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या-2 सन् 1974) से है;

(ख) "अनुसूची" का तात्पर्य इस योजना से संलग्न अनुसूची से है;

(ग) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;

(घ) "पीड़ित व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो कि अपराध के परिणाम-स्वरूप क्षति या हानि से पीड़ित हो और पुनर्वास की आवश्यकता हो और इसमें पीड़ित के परिवारिक सदस्य भी सम्मिलित हैं;

(ङ) "जिला विधिक सेवा अधिकरण" का तात्पर्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 9 के अधीन गठित जिला प्राधिकरण से है;

(च) "राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण" का तात्पर्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 के अधीन गठित राज्य प्राधिकरण से है;



पीड़ित क्षतिपूर्ति  
निधि

3-(1) "पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि" के नाम से निधि गठित की जायेगी जिससे ऐसे पीड़ितों या उनके आश्रितों, जिन्हें अपराध के कारण क्षति या हानि हुई है और पुनर्वास की आवश्यकता है, को क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष इस योजना के प्रयोजनार्थ पृथक रूप से बजट आवंटित करेगी।

(3) निधि का संचालन सचिव, राज्य विधिक सेवा अधिकरण द्वारा किया जायेगा।

क्षतिपूर्ति के लिए  
पात्रता

4-पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिए पात्र होगा यदि:-

(क) अपराधी का पता नहीं चलता है या उसकी शिनाख्त नहीं की जाती है, किन्तु पीड़ित की शिनाख्त हो जाती है, और जहां कोई विचारण नहीं होता है, वहाँ ऐसे पीड़ित या उसके आश्रित अधिनियम की धारा 357-क की उपधारा (4) के अधीन क्षतिपूर्ति की स्वीकृति के लिए आवेदन कर सकते हैं;

(ख) पीड़ित/दावेदार ने घटना से 48 घण्टे के भीतर पुलिस स्टेशन के अधिकारी या प्रभारी, क्षेत्र के किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या कार्यकारी मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपराध की रिपोर्ट की हो, परन्तु यह कि यदि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे, संतुष्ट हो जाता है तो रिपोर्ट करने में हुए विलम्ब को माफ कर सकता है;

(ग) पीड़ित/दावेदार ने मामले के अन्वेषण और विचारण के दौरान पुलिस तथा अभियोजन पक्ष को सहयोग दिया है।

क्षतिपूर्ति देने के  
लिए प्रक्रिया

5-(1) जब कभी न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 357-क की उपधारा (2) के अधीन संस्तुति की जाती है या कोई आवेदन किसी पीड़ित या उसके आश्रित द्वारा अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को किया जाता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मामले की जांच करेगा और रिपोर्ट की गयी अपराधिक गतिविधि में पीड़ित को हुई हानि या क्षति के सम्बन्ध में दावे के विषय वस्तु को सत्यापित करेगा। दावे की वास्तविकता निर्धारित करने के लिए कोई अन्य आवश्यक सुसंगत सूचना मांग सकता है। दावों का सत्यापन करने और सम्यक जांच के उपरान्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस योजना के प्राविधानों के अनुसार अधिनियम की धारा 357-क की उपधारा (4) के अधीन न्यायालय की संस्वीकृति की प्राप्ति या आवेदन-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से दो मास के भीतर क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा।

(2) इस योजना के अधीन क्षतिपूर्ति इस शर्त के अधीन भुगतान की जायेगी कि यदि विचारण न्यायालय पश्चातवर्ती तिथि को निर्णय देते समय दोषी व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 357 की उपधारा (3) के अधीन क्षतिपूर्ति की राशि के रूप में किसी राशि का भुगतान करने के लिए आदेश देता है, तो पीड़ित या दावेदार क्षतिपूर्ति की धनराशि के बराबर आदेशित धनराशि या उपधारा 3 के अधीन दी जाने वाली आदेशित धनराशि जो भी कम हो, विप्रेषित करेगा। पीड़ित व्यक्ति/दावेदार से इस आशय की, अण्डरटैकिंग निधि से धनराशि वितरित करने से पूर्व प्राप्त की जायेगी।

(3) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित को हुई क्षति के आधार पर पीड़ित या उसके आश्रित को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की मात्रा, उपचार पर उपगत होने वाले चिकित्सा व्यय, अत्येष्टि व्यय इत्यादि के रूप में ऐसे आकस्मिक प्रभार सहित पुनर्वास के लिए अपेक्षित न्यूनतम आजीविका राशि का निर्णय करेगा। प्रत्येक प्रकरण में तथ्यों के आधार पर प्रकरणवार प्रत्येक पीड़ित के लिए क्षतिपूर्ति भिन्न-भिन्न हो सकती है।

(4) कतिपय मामलों में अपराध की अतिसंवेदनशीलता एवं पीड़ित व्यक्ति की विशेष आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विशेष मामलों में जिला विधिक सेवा अधिकरण या राज्य विधिक सेवा अधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, को अधिकार होगा कि रुपये 25 हजार तक, अधिकतम 1.00 लाख की सहायता उपलब्ध करा सकते हैं जैसे-

(क) जहां पीड़ित, नाबालिग लड़की हो और विशिष्ट उपचार व देखभाल की आवश्यकता हो।



(ख) जहाँ पीड़ित, मानसिक रूप से आहत हो और विशिष्ट उपचार व देखभाल की आवश्यकता हो।

(ग) किसी अन्य मामले में, जैसा संबंधित विधिक सेवा अधिकरण उचित समझे।

(5) पीड़ित या उसके आश्रितों को दिये जाने वाली क्षतिपूर्ति की मात्रा अनुसूची एक में वर्णित सीमा से अधिक नहीं होगी।

(6) इस योजना के अधीन निर्णीत क्षतिपूर्ति की राशि पीड़ित या उसके आश्रितों, जैसी स्थिति हो, को निधि से वितरित की जायेगी। अन्तरिम या अन्तिम वित्तीय सहायता जैसे भी स्थिति हो, का भुगतान आवेदक के बैंक खाते में अधिमानतः एक सप्ताह के अन्दर की जायेगी। यदि पीड़ित व्यक्ति नाबालिग है तो धनराशि का भुगतान पीड़ित के माता-पिता या अभिभावक के खाते में क्षतिपूर्ति की धनराशि समुचित के सदुपयोग के बारे में संतुष्ट हो जाने पर संबंधित अधिकरण द्वारा की जायेगी।

(7) पीड़ित द्वारा प्ररनगत अपराध के सम्बन्ध में केन्द्र एवं राज्य से प्राप्त क्षतिपूर्ति अर्थात् बीमा अनुग्रह, किसी अन्य अधिनियम में प्राप्त या केन्द्र एवं राज्य द्वारा चलायी जा रही किसी अन्य योजना के अधीन प्राप्त भुगतान भी इस योजना के अधीन क्षतिपूर्ति राशि के भाग के रूप में मानी जायेगी। यदि क्षतिपूर्ति की राशि पीड़ित द्वारा उपरोक्त वर्णित स्रोतों से प्राप्त भुगतान से अधिक है तो शेष राशि का भुगतान निधि से किया जायेगा।

(8) मोटर वेहिकल ऐक्ट, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) से आच्छादित मामले, जिनमें मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिबुनल द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान करने के आदेश दिये गये हैं, इस योजना से आच्छादित नहीं होंगे।

(9) राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यथास्थिति, पीड़ित की पीड़ा कम करने के लिये तुरन्त ही प्राथमिक चिकित्सा अथवा चिकित्सीय लाभ के लिये आदेश कर सकेगा जो पुलिस थाने के गार साधक अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के पुलिस अधिकारी या सम्बन्धित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाणपत्र पर मुफ्त उपलब्ध कराये जायेगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अन्य ऐसे अन्तरिम अनुतोष दिये जाने के लिए ऐसे आदेश दे सकेंगे, जैसा समुचित प्राधिकारी उचित समझे।

6-क्षतिपूर्ति व पुनर्वास सेवार्यें प्रदान करने का निर्धारण करते समय पीड़ित की मूलभूत पुनर्वास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिकरण निम्नलिखित तथ्यों द्वारा निर्देशित होगा:-

(क) पीड़ित व्यक्ति को आई चोटें, घाव के प्रकार व गम्भीरता तथा उसे होने वाले चिकित्सीय एवं मानसिक उपचार पर होने वाले व्यय।

(ख) पीड़ित की उम्र व आर्थिक स्थिति के कम में उसकी शैक्षिक व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकताओं, जैसे भी स्थित हो।

(ग) पीड़ित को जहाँ गैर आर्थिक नुकसान, मानसिक या भावनात्मक आघात या अपमान का सामना करना पड़ा हो।

(घ) किसी वैकल्पिक आवास के प्राविधान करने के संबंध में होने वाला व्यय जहाँ पीड़ित अपराध घटित होने और प्राथमिकी दर्ज होने या अपराधिक वा. प्रारम्भ होने से भिन्न स्थान पर रहता हो।

7-इस योजना के अधीन पारित क्षतिपूर्ति आदेश की प्रति को विचारण न्यायालय के अभिलेख पर लाना आवश्यक होगा ताकि न्यायालय अधिनियम की धारा 357 की उपधारा (3) के अधीन क्षतिपूर्ति का आदेश पारित कर सके।

8-अधिनियम की धारा 357-क की उपधारा (4) के अधीन पीड़ित या उसके आश्रित द्वारा अपराध की एक वर्ष की अवधि के बाद किये गये किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा :

परन्तु, यह कि यदि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिलिखित कारणों से सन्तुष्ट हो जाता है तो वह दावा दायर करने में हुए विलम्ब को माफ कर सकता है।

पीड़ित व्यक्ति को सहायता के निर्धारण करने हेतु निर्देशक सिद्धान्त

अभिलेख पर रखे जाने वाले आदेश परिसीमा

परिसीमा

अपील

9-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति से इन्कार करने से व्यथित व्यक्ति 90 दिन के अन्दर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

परन्तु यह कि यदि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का ऐसे कारणों से, जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, अपील दायर करने में हुए विलम्ब को माफ कर सकता है।

एस0के0 रघुवंशी,  
सचिव।

### अनुसूची-1

क्र०सं०	हानि या क्षति का विवरण	क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
1	बलात्कार	रु० 2,00,000/-
2	मानसिक संताप के कारण हुई हानि या क्षति	रु० 1,00,000/-
3	संक्षारक पदार्थ अर्थात् तेजाब आदि हमले से पीड़ित	रु० 3,00,000/-
4	मृत्यु (गैर कमाने वाले सदस्य)	रु० 1,50,000/-
5	मृत्यु (कमाने वाले सदस्य)	रु० 2,00,000/-
6	मानव तस्करी से पीड़ित	रु० 2,00,000/-

आज्ञा से,  
एस0के0 रघुवंशी,  
सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No.-653/VI-P-9-2014-31(90)/2010 Dated April 9, 2014.

No.-653/VI-P-9-2014-31(90)/2010.

Lucknow, Dated April 09, 2014

In exercise of the powers conferred by section 357-A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974), the Governor of Uttar Pradesh, in co-ordination with the Central Government, hereby frames the following scheme for providing funds for the purpose of compensation to the victim or his dependents who have suffered loss or injury as a result of the crime and who require rehabilitation, namely :

#### THE UTTAR PRADESH VICTIM COMPENSATION SCHEME

Short title

1. This Scheme may be called the Uttar Pradesh Victim Compensation Scheme, 2014

Definitions

2. In this Scheme, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No.-2 of 1974);

(b) "Schedule" means the Schedule appended to this Scheme;

(c) "State" means the State of Uttar Pradesh;

(d) "Victim" means a person who himself has suffered loss or injury as a result of the crime and requires rehabilitation, and includes his dependent family members;



(e) "District Legal Services Authority" means the District Authority constituted under Section 9 of the Legal Services Authorities Act, 1987.

(f) "State Legal Services Authority" means the State Authority constituted under section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987.

3. (1) There shall be established a fund namely Victim Compensation Fund from which amount of compensation under this Scheme shall be paid to the victim or his dependents who have suffered loss or injury as result of the crime and who require rehabilitation.

Victim  
Compensation  
Fund

(2) The State Government shall allot a separate budget for the purpose of the Scheme every year.

(3) The Fund shall be operated by the Secretary, State Legal Services Authority.

4. A victim shall be eligible for the grant of compensation if :

Eligibility for  
compensation

(a) the offender is not traced or identified, but the victim is identified and where no trial takes place; such victim may also apply for grant of compensation under sub section (4) of section 357-A of the Act;

(b) the victim/claimant reports the crime to the officer-in-charge of the police station within 48 hours of the occurrence or any senior police officer or Executive Magistrate or Judicial Magistrate of the area provided that the District Legal Services Authority, if satisfied for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in reporting;

(c) the victim/claimant cooperates with the police and the prosecution during the investigation and trial of the case.

5. (1) Whenever a recommendation is made by the Court or an application is made by any victim or his dependent under sub section (2) of section 357-A of the Act to the District Legal Services Authority, the District Legal Services Authority shall examine the case and verify the contents of the claim with regard to the loss or injury caused to the victim and arising out of the reported criminal activity and may call for any other relevant information necessary in order to determine genuineness of the claim. After verifying the claim, the District Legal Services Authority shall, after due enquiry, award compensation within two months from the date of receipt of the recommendation of the court of the receipt of application under sub-section (4) of section 357-A of the Act in accordance with the provisions of this Scheme.

Procedure for  
grant of  
compensation

(2) Compensation under this Scheme shall be paid subject to the condition that if the trial court, while passing judgment at later date, orders the accused persons to pay any amount by way of compensation under sub-section (3) of section 357 of the Act, the victim/claimant shall remit an amount ordered equal to the amount of compensation or the amount ordered to be paid under the said sub-section (3) whichever is less. An undertaking to this effect shall be given by the victim/ claimant before the distribution of the compensation amount.

(3) The District Legal Services Authority shall decide the quantum of compensation to be awarded to the victim or his dependents on the basis of loss caused to the victim, medical expenses to be incurred on treatment, minimum sustenance amount required for rehabilitation including such incidental charges as funeral expenses etc. The compensation may vary from case to case depending on the facts of each case.

(4) Keeping in view the particular vulnerabilities and special needs of the affected person in certain cases, the District Legal Services Authority or the State Legal Services Authority, as the case may be, will have the power to provide additional assistance of Rs. 25,000/- subject to maximum of Rs. 1,00,000/-, in the cases where:

(a) The affected person is a minor girl requiring specialized treatment and care:

(b) The person is mentally challenged requiring specialized treatment and care;

(c) Any other case as may be deemed fit by the Legal Services Authority concerned.

(5) The quantum of compensation to be awarded to the victim or his dependents shall not exceed the maximum limit as per Schedule-1.

(6) The amount of compensation decided under the Scheme shall be disbursed to the victim or his dependents, as the case may be, from the Fund. The interim or final financial assistance, as the case may be, shall be remitted to the bank account of the applicant preferably within a week. In cases where the person affected is a minor, the amount shall be remitted to the bank account of his parent or guardian after the Authority concerned is satisfied about the proper utilization of the amount of compensation.

(7) Compensation received by the victim from the State in relation to the crime in question, namely, insurance, *ex-gratia* and/or payment received under any other Act or State-run Scheme, shall be considered as part of the compensation amount under this Scheme and if the due compensation amount exceeds the payments received by the victim from collateral sources mentioned above, the balance amount shall be paid out of the Fund.

(8) The cases covered under the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) wherein compensation is to be awarded by the Motor Accident Claims Tribunal, shall not be covered under this Scheme.

(9) The District Legal Services Authority, to alleviate the suffering of the victim, may order for immediate first-aid facility or medical benefits to be made available free of cost on the certificate of the police officer not below the rank of the officer-in-charge of the police station or the Magistrate of the area concerned. The district Legal Services Authority may order for any other interim relief as it may deem fit.

Principles governing the determination of assistance to the affected person

6. While determining the compensation and rehabilitation services to be provided on the basis of the restorative needs of the affected person, the Authority shall be guided by the following factors:

(a) Type and severity of the bodily injury suffered by the affected person and expenditure incurred or likely to be incurred on victim's medical treatment and psychological counseling.

(b) Age and financial condition of the affected person so as to determine the need for his education or professional or vocational training, as the case may be.

(c) Non-pecuniary loss entailing suffering, mental or emotional trauma or humiliation faced.

(d) Expenses incurred in connection with provision of any alternate accommodation in cases where the affected person resides in a place other than where the offence was committed and the FIR has been recorded and/or criminal trial initiated.

Order to be placed on record

7. Copy of the order of compensation passed under this Scheme shall be mandatorily placed on record of the trial court to enable the court to pass order of compensation under sub-section (3) of section 357 of the Act.

Limitation

8. No claim made by the victim or his dependents under sub-section (4) of section 357-A of the Act shall be entertained after a period of six months of the crime:

Provided that the District Legal Services Authority, if satisfied for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in filing any claim.



9. Any victim aggrieved of the denial of compensation by the District Legal Services Authority may file an appeal before the State Legal Services Authority within a period of ninety days : Appeal

Provided that the State Legal Services Authority, if satisfied for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in filing the appeal.

S.K. RAGHUVANSHI,  
*Sachiv.*

### Schedule - 1

	Particulars of loss or injury	Maximum limit of compensation
1	Rape	Rs. 2,00,000/-
2	Loss or injury causing severe mental agony to the victim of the crime	Rs. 1,00,000/-
3	Victim of corrosive substance <i>i.e.</i> acid attack etc.	Rs. 3,00,000/-
4	Death (Non-earning member)	Rs. 1,50,000/-
5	Death (Earning member)	Rs. 2,00,000/-
6	Victim of Human Trafficking	Rs. 2,00,000/-

By order,  
S.K. RAGHUVANSHI,  
*Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 42 राजपत्र (हि०)-2014-(154)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।  
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 3 सां० गृह-2014-(155)-5000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

1769  
22/7/15

प्रेषक,  
कमल सक्सेना,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0शासन।
- 2- सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ।
- 3- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

**गृह(पुलिस)अनुभाग-15**

लखनऊ:दिनांक 24 जुलाई, 2015

विषय:-उ0प्र0पीडित क्षतिपूर्ति योजना-2014 के संबंध में निर्गत संशोधित अधिसूचना 10.07.2015 के क्रियान्वयन के संबंध में।

S.R. Lal  
22-7-15

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनहित याचिका संख्या-4579/2015 गुड़िया स्वयं सेवी संस्थान बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.06.2015 के अनुपालन में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 (पाक्सो एक्ट-2012) की ~~सेक्~~ 4,6,7,9,11 एवं 14 के अधीन अपराध को उ0प्र0पीडित क्षतिपूर्ति योजना, 2014 में सम्मिलित करते हुए अधिसूचना संख्या-1986/छ:-पु0-9-15-31(90)/2010, दिनांक 10 जुलाई, 2015 अधिसूचित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

2. उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करे।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

22.7.2015  
(कमल सक्सेना)  
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(पी0एन0 सिंह)  
उप सचिव।



20/07/2015  
10-7-15

**UTTAR PRADESH SHASAN**  
Grih (Police) Anubhag- 9

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.-1986/VI-P-9-2015-31(90)/2010 dated: July 10, 2015.

NOTIFICATION

No.-1986/VI-P-9-2015-31(90)/2010.  
Lucknow: Dated: July 10, 2015.

In exercise of the powers under section 357-A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no 2 of 1974), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor in coordination with the Central Government, is pleased to make the following amendment in Government notification no-653/VI-P-9-2014-31(90)/2010 dated April 09, 2014, regarding the Uttar Pradesh Victim Compensation Scheme, 2014 :

AMENDMENT

In the aforesaid notification, in Schedule-1 after Serial no.-6, the following Serial shall be inserted,

7- Offences under section 4,6,7, 9, 11 and 14 of the Protection of the Children from Sexual offences Act-2012;

(a) Penetrative Sexual assault (Section-4)	Rs-2,00,000/-
(b) Aggravated penetrative Sexual assault (Section -6)	Rs-2,00,000/-
(c) Sexual assault (Section-7)	Rs-1,00,000/-
(d) Aggravated Sexual assault (Section- 9)	Rs-1,50,000/-
(e) Sexual harrassment (Section-11)	Rs-1,00,000/-
(f) Using Child for Pornographic purpose (Section-14)	Rs-1,00,000/-

9/7/15  
9-7-15

By Order

(Neena Shanna)  
Sd/-

उत्तर प्रदेश शासन  
गृह (पुलिस) अनुभाग-9  
संख्या-1986/छ:-पु0-9-15-31(90)/2010  
लखनऊ: दिनांक: 10 जुलाई, 2015

### अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10, सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम संख्या-2, सन् 1974) की धारा 357-क के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल केन्द्र सरकार से समन्वय करके उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2014 से संबंधित सरकारी अधिसूचना संख्या-653/छ:-पु0-9-2014-31(90)/2010, दिनांक 09 अप्रैल, 2014 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं:-

#### संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, अनुसूची-1 में, कम संख्या-6 के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक बढ़ा दिया जायेगा:-

7. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-4, 6, 7, 9, 11 और 14 के अधीन अपराध	
(क) प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा-4)	₹ 2,00,000/-
(ख) गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा-6)	₹ 2,00,000/-
(ग) लैंगिक हमला (धारा-7)	₹ 1,00,000/-
(घ) गुरुत्तर लैंगिक हमला (धारा-9)	₹ 1,50,000/-
(ङ) लैंगिक उत्पीड़न (धारा-11)	₹ 1,00,000/-
(च) अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग (धारा-14)	₹ 1,00,000/-

आज्ञा से


मीना शर्मा  
सचिव।



उत्तर प्रदेश शासन  
गृह (पुलिस) अनुभाग-9  
संख्या-1986/छ-पु0-9-15-31(90)/2010  
लखनऊ: दिनांक: 10 जुलाई, 2015

उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2014 में संशोधन की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (3) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
- (4) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (5) महानिदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (6) समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- (7) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- (8) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना जन साधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
- (9) निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को उक्त अधिसूचना गृह विभाग की वेबसाइट पर लोड करने हेतु प्रेषित।
- (10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(अमर सेन सिंह)  
संयुक्त सचिव।